



एक बार एक ऑल्लेन में सारी मांगें मान ली गईं। नैने नेताजी से पूछा कि सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या उन्हें लोकतंत्र की चिंता नहीं है? उन्होंने कहा उससे लिए सरकार को पहले आमनी चिंता करनी पड़ती है। सरकार लोकतंत्र की चिंता कर सके, इसके लिए जरूरी है कि वह बनी रहे। उनकी बात बिस्फुल्ल ठीक है। यह सरकार का विशेषाधिकार है कि वह लोकतंत्र की चिंता किस विधि से करती है। इसमें कोई दूसरा दखल नहीं दे सकता है।

चिंतन

उपचुनाव में हार भाजपा के
लिए आत्ममंथन का समय

[illegible]

आर्थिकी
ऋषभ मिश्रा

भविष्य की मुद्रा व्यवस्था और भारत का पॉलीमर प्रयोग

[illegible]

(लेखक स्वतंत्र प्रकार हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)



विचार
डॉ. संजय शुक्ला

[illegible]

परिचायक था। कुछेक प्रोटेस्ट्स को देश के दुकड़े-दुकड़े करने की दमोक्ति करते हुए भी देश गये देशकंद युवाओं के इस बड़बुनारी के लिए कुल लोग जिम्मेदार हैं जो देश के जन जी को लगाने नेपाल और बांग्लादेश की तरह सड़कों पर उतरने लिए उकसाते रहे हैं। इधर सोशल मीडिया पर कुल युट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पत्रकार लेखक - लेखिका और हस्तकवित्र इन बड़बुन प्रोटेस्ट्स की भाषा और हकमती के 'जस्टिस' करने में जुटे हैं लेकिन यह हर लिहाज से असवीकार्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता से असहमति और

[illegible]

अलुतना छात्रों और युवाओं के समुह को का-
नाना थो कि केंद्र सरकार ने पचास सत्रों सत्र
लोक परिषद (अनुसूचित साधनों की गैकभम
अधिपतिपन) 2024 में आवेकक सेशीन सत्र को
जहाँ लोक परिषद (अनुसूचित साधनों की गैकभम
अधिपतिपन) 2024 में आवेकक सेशीन सत्र को
पेर लीन मालुनी की त्वरित और समायोज्य सत्र
के फाट्ट ईके कोरें सत्रों के सत्रों के सत्रों के
इसके सत्रों के सत्रों के सत्रों के सत्रों के
10 करोड़ नुनुरीन का प्रयास है। फाट्ट ईके कोरें
चाइरशॉट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर
फैसला होने अनाइक
किना मी है। रागुपति के
मंजुरी के बाद यह सत्रों के
लागू हो है। इससे
आकर सरकार ने प्रयास
और परिषद प्रयास
सुचार के लिए टेनलीन
एकपत्र देन लीकल
को अग्रिम सत्रों के
सत्रों के सत्रों के सत्रों के
टाइक पोस करीन का
गदन किना है। इस सत्रों के

का मुख् उद्देश्य परिषद प्रयास की फुल प्रमोशन के
के साथ हो परिषदों को पारदर्शी व तकनीकी
आधारित करने की है।

विचारगोष्ठी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में कोई भी अंदोलन हर राजनीतिक नहीं हो सकता। बाद हाथिया 'सिरीजी' के प्रोटोकॉल की कड़े तो पाई' के संस्थापक अजीम उद्दिन एके ने हर राजनीतिक नहीं हो सकता लेकिन बाद में अंदोलन की दिशा 'राजनीतिक' हो गई। सच प्रमाणित ने मुआवजा में इस प्रश्न को काफी हद तक हल किया लेकिन पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सोम बांधुपुत्र के भूख हड़ताल और पुलिस ब्रह्म अंदोलन' जैसी अस्पताल में भर्ती करके बाद ब्रह्म अंदोलन' के हर हिस्से में पहुंच गया 'सिरीजी' के 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों और युवाओं के चलो संसद मार्च' के दौरान प्रदर्शनकर्ताओं पर 'पूजितिया लाली बाई और अश्रुमयौ छोड़ने की घटना' ने जमाने की जो कागज किया।

बहरहाल यह अंदोलन इस्कोमिटी' संदी में 2011 और 2012 में मुआवजा अंदोलन और निर्माण अंदोलन के लिहाज से अलग तरह लिखा हुआ है भारत में सोसाल मीडिया ने राजनीति और अंदोलन

आठ वर्षों में पल्लवी बारा दसक 2009 के आसपास ही सार्वजनिक सेवाओं में लौटने की 2012 में आम चुनाव और नित्या आंदोलनों में इस्तेमाल आने से इच्छा साधक विधान, इस दोनों आंदोलन को अलग-अलग लड़ने में मुख्य भूमिका छात्रों और युवाओं की रचना उन्होंने सोशाल मिडिया का सहकार्य अपने आंदोलनों में किया। युवाओं में प्रभुत्व और विद्युत के जरूरत आने के अलग-अलग और निम्न के साथ समुचित धुमके और हत्या के आक्रोश और पाठ्यक्रम और दुर्न्याय का लड़ने पल्लवी युवाओं के नवाचार और प्रभाव है कि लोगों ने पल्लवी बारा सकारात्मक और राजनैतिकों की सार्वजनिक आलोचना सोशाल मिडिया प्लेटफॉर्मों पर की जितने एक मजबूत राजनैतिक नैतिकता पल्लवी का सोशाल मिडिया है इस नैतिकता के ही अंतर यह कि साल 2014 आम चुनाव में पल्लवी को सार्वजनिक शक्ति का समर्थक पड़ा। देश ने इसी तरह आंदोलन 2014 सुप्रसिद्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन जेपी अंगुष्ठांगुली हथु छात्रों और युवाओं के आंदोलन के रूप में भी देखा था।

[illegible]

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को मिला है देवता का दर्जा

[illegible]

संकलि
दर्शव



संकलि
प्रेरण

અંતર્મજ



करंट अफेयर

[illegible][illegible]

डबर सरक्षा के लिए ज

हमारे देश में साइबर फ्रॉड के मामले बहुत

[illegible]

- प्रशांत शुक्ला

ऑफ बीट

नशामुक्त यूथ, नशामुक्त
विकसित भारत

[illegible]

-ममता शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अध्यापिका

संगी मिश्रण सेवा संस्थान जरा मुक्ति के

अपने विचार

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स :
0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से
bhagnati@gmail.com पर भेज सकते हैं।



पहला सोमवार

जम्मू : सावन के पहले सोमवार को रणवीरेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करती एक श्रद्धालु।

बोल

दुनिया के पास पैट्रियट मिसाइलें हैं। अब जरूरी बात यह है कि हमारे सहयोगी जरूरी सामग्री देने पर राजनीतिक फैसला लें। अमेरिका जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। यूरोप भी यह जानता है। - व्लादीमीर जेलेन्स्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति



बोल

दुनियाभर में संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में सुरक्षा परिषद की अक्षमता को लेकर सदस्य देशों और वैश्विक नागरिकों में साफ तौर पर निराशा है। व्यापक सुधार की आवश्यकता पहले से कही अधिक स्पष्ट है। - पी हरीश, संसद में भारत के राजदूत



सम-सामयिक

नेपाल: जेन जी अब बालेन की सरकार के खिलाफ सड़कों पर

जनसत्ता संवाद

नेपाल में युवा वर्ग अब प्रधानमंत्री बालेन शाह के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगा है। जेन-जी के समर्थन के जरिए सरकार बनाने वाले शाह को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जिस बालेन शाह को अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'टाइम' ने वर्ष 2023 के शीर्ष सौ उभरते नेताओं में शामिल किया था, उनकी तुलना अब जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की जा रही है।

नेपाल में 10 जुलाई को आत्मदाह करने वाले 25 वर्षीय युवक गणेश नेपाली का चेहरा सरकार के खिलाफ विरोध व असंतोष का प्रतीक बन गया है।

शाह की सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने, विवादित अध्यादेश लाने और कूटनीतिक मोर्चों पर अनुभवहीनता से देश की किरकिरी कराने के आरोप लग रहे हैं। ताजा विरोध 25 वर्षीय गणेश नेपाली नामक एक युवक द्वारा आत्मदाह करने के बाद शुरू हुआ है। गणेश एक मोटरसाइकिल-टैक्सी चला कर अपना परिवार चलाते थे। 10 जुलाई को काठमांडू में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर कथित तौर पर रास्ता अवरुद्ध करने के आरोप में पुलिस ने उसके वाहन के पहियों पर 'व्हील लाक' लगा दिया। गणेश ने इसका विरोध किया और इसे लेकर पुलिस से उसकी तीखी झड़प भी हुई। पुलिस के रवैये से हताश होकर गणेश ने अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल खुद पर छिड़क कर आग लगा ली। साठ फीसद तक जल चुके गणेश की एक दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना के विरोध में लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर गए और तोड़फोड़ की।

हालात बेकाबू होता देख सरकार ने आपदा प्रबंधन की कोशिश शुरू की। गणेश की मौत मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच समिति का गठन करने, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी, बेटी की शिक्षा का

खर्च उठाने तथा दोषी पुलिसकर्मियों को निर्लंबित करने की घोषणा की।

दरअसल, सरकार के खिलाफ विरोध की आग कई और मुद्दों को लेकर पहले से सुलग रही थी। बालेन सरकार के कई फैसलों - मजदूर संगठनों और छात्र संघों को बंग करना, संसद को दरकिनार कर अध्यादेश लाना, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर लोगों को बेदखल करना, पुलिस की बर्बरता, सरकार का विरोध करने वालों की गिरफ्तारी और संसद में सरकार के विरोधाभासी बयान से लोग पहले से ही नाराज चल रहे थे।

ठेके पर नियुक्त लगभग 50 हजार कर्मचारी शाह सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मुंह चुराने का आरोप तब लगा, जब 30 अप्रैल से शुरू होने वाला संसद का सत्र टाल कर 11 मई कर दिया गया और इस दौरान आठ अध्यादेश लागू कर दिए गए। न्यायिक नियुक्तियों में वरिष्ठता के क्रम को नजरअंदाज किए जाने की भी खूब आलोचना हुई। वहीं, सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए करीब 1,600 लोगों की नौकरियां खत्म कर दीं। चीन, भारत और अमेरिका के साथ विदेश नीति को लेकर भी विपक्ष बालेन सरकार पर अनुभवहीनता के आरोप लगा रहा है।

एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में सरकार ने काठमांडू सहित देश के विभिन्न हिस्सों में अतिक्रमण के नाम पर भूमिहीन लोगों के अस्थायी निर्माण को हटाकर करीब 2,600 परिवारों को बेदखल कर दिया। इनमें से करीब तीन सौ से अधिक परिवार काठमांडू के विभिन्न हिस्सों में बनाए गए अस्थायी आवास केंद्रों में रहने लगे, लेकिन सरकार ने दो जुलाई को इन केंद्रों को भी खाली करने का आदेश दिया। मधेश प्रदेश के रौतहट निवासी सोरंग थापा कहते हैं, नदी किनारे बसी अवैध बस्तियों को बालेन उसी समय से हटाना चाहते थे, जब वे काठमांडू के मेयर हुआ करते थे। इन्हें पुलिस व सेना का सहारा लेकर हटा दिया गया।



जानें-समझें

किस मोड़ पर भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम

अचानक क्यों बढ़ रही हैं इसरो की चुनौतियां

जनसत्ता संवाद

भारत के अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रमों को लेकर इन दिनों अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। देश की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी- इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) कई अभिय कारणों से चर्चा में है। यह संस्थान पिछले छह दशकों में कड़ी मेहनत और सूझ-बूझ से खड़ा किया गया है। हाल में कई असफल प्रक्षेपण, अहम परियोजनाओं की धीमी गति, वैज्ञानिकों के नौकरी छोड़ने और धरेलू नवउद्यम की चुनौती का सामना इसरो को करना पड़ रहा है। ये घटनाएं भले ही अलग-अलग लगें, लेकिन इनका व्यापक असर पड़ा है। हाल में जिन बड़े वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ी है, उनमें एक वर्ष 2023 में चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े थे। वर्ष 2018 के बाद से देश में निजी कंपनियों के कई संस्थापक और कर्मचारी इसरो के पूर्व युवा वैज्ञानिक ही हैं।

हाल की असफलताएं

इसरो के भरोसेमंद पीएसएलवी राकेट के दो नए संस्करण पीएसएलवी सी61 और सी 62 के प्रक्षेपण क्रमशः 18 मई, 2025 और 12 जनवरी, 2026 को किए गए और दोनों ही बार असफलता हाथ लगी। 'गगनयान' के लिए पहली बिना-इंसान वाली परीक्षण उड़ान 'जी1' को तैयार करने में देरी हुई। 14 जुलाई को भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का एक आंतरिक प्रपत्र मीडिया में चर्चा में आया, जिसमें 'गगनयान' जैसी परियोजनाओं से जुड़े कुछ वैज्ञानिकों को नौकरी छोड़ने से रोकने की जरूरत बताई गई। इसरो के कुछ पूर्व वैज्ञानिक मानते हैं कि भरोसेमंद पीएसएलवी राकेट की लगातार दो नाकामियों की वजह से मनेबल काफी गिर गया है। पीएसएलवी सी62 मिशन की नाकामी के बाद से इसरो का कोई प्रक्षेपण नहीं हुआ है, जबकि इस साल सात से आठ मिशन की योजना थी।

प्रतिभा पलायन

अंतरिक्ष विभाग के प्रपत्र में इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों की ओर से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के पत्र आए इस्तीफे का जिक्र किया गया है। इनमें वे कर्मचारी भी शामिल थे जो प्रतिष्ठित गगनयान और दूसरे अहम मिशन/परियोजनाओं से जुड़े थे, और जिनके इस्तीफे या स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति से राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर बुधा



(फाइल फोटो)



किसी बड़ी परियोजना में देरी की स्थिति में आप लंबे समय तक कार्यबल को रोक नहीं सकते। गगनयान मिशन पर काम करने वाले लोग इसे छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता कि वे अपनी जिंदगी में इसे पूरा होते शायद ही देख पाएंगे। - एम अन्नादुरई

चंद्रयान-1 व मंगलयान के निदेशक



निजी क्षेत्र को छोटे काम सौंपने से इसरो सिर्फ बड़े शोध पर ध्यान देगा। यह एक सोची-समझी योजना है। मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। अगर हमें छोटे उपग्रह और पृथ्वी की निचली कक्षा के बाजार में फायदा उठाना है, तो निजी कंपनियां जरूरी हैं। - पीवी वेंकटकृष्णन, इसरो को पूर्व निदेशक

असर पड़ने की आशंका है। प्रपत्र में कहा गया है कि इस्तीफे मंजूर न किए जाएं। इसरो से पिछले एक साल में एक सौ से ज्यादा कर्मचारी निकल गए हैं।

चुनौतियां का दौर

इसरो के एक पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने अपने 37 साल के करिअर में लोगों के संस्थान छोड़ने की तीन लहरें देखी हैं। पहली लहर 1980 के दशक के आखिर में आई थी, जब इंजीनियर तेल के कुओं (आयल रिस) में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों के लिए खाड़ी देशों में चले गए थे। दूसरी लहर 1990 के दशक की शुरुआत में आई, जब लोग दूरसंचार उद्योग में शामिल होने के लिए चले गए। सबसे बड़ी लहर 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक

की शुरुआत में आई, जब लोग सूचना तकनीक उद्योग में चले गए। अब नव उद्यम की ओर पलायन शुरू हुआ है।

मंजूर पद ज्यादा, कर्मचारी कम

तीन दशकों की सालाना रिपोर्ट से पता चलता है कि अभी मंजूर पदों के मुकाबले मौजूद कर्मचारियों की संख्या 72 फीसद है, जो हाल के समय में सबसे कम है (इससे पहले 2013-14 में यह आंकड़ा 76% था)। वर्ष 2017-18 में 16,902 पदों में से 95% पद भरे हुए थे, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा था। एक पूर्व वैज्ञानिक के मुताबिक, अगर किसी परियोजना में अनिश्चितता होती है, तो जुड़े लोग नौकरी छोड़ सकते हैं। ज्यादातर वे युवा नौकरी छोड़ रहे हैं, जिन्हें लगभग 10-12 साल का अनुभव है।

- प्रस्तुति : दीपक रस्तोगी



विश्व परिक्रमा

ब्रिटेन: डाउनिंग स्ट्रीट के अलावा मैनचेस्टर भी बना सत्ता का केंद्र

जनसत्ता संवाद

लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास से लगभग 260 किलोमीटर दूर साधारण सा दिखने वाला आधुनिक कार्यालय खंड ब्रिटेन में सत्ता का एक और नया केंद्र बन गया है। मैनचेस्टर स्थित यह साधारण इमारत 'नंबर 10 नार्थ' है। यह नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम की उस पहल का प्रमुख केंद्र है, जिसके जरिए वह ब्रिटेन को एक अलग और नए अंदाज का नेतृत्व देने का वादा कर रहे हैं।

राष्ट्रीय राजनीति में लौटने से पहले बर्नहैम ग्रेटर मैनचेस्टर के महापौर थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके आरंभिक कार्यों में से एक, इस शहर में कार्यालय खोलना



रहा। यह स्थानीय नेताओं को ज्यादा अधिकार देने और आर्थिक विकास को फैलाने के वादे का प्रतीक और इंजन,

निजी कंपनियों की दस्तक

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 23 जुलाई को संसद में बताया कि भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले नवउद्यम की संख्या 2014 में एक थी। वर्ष 2026 तक ऐसी कंपनियों की संख्या बढ़कर चार सौ हो गई है। निजी वित्तपोषण भी 2021-22 में 100.5 मिलियन डालर से बढ़कर 618.5 मिलियन डालर हो गया है। सरकार ने 2023 में नई अंतरिक्ष नीति बनाई, जिससे निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला। निजी कंपनियों में स्काईरुट एअरोस्पेस, अग्निकुल कासमास, एस्ट्रोबेस, पिक्सेल, बेलाट्रिक्स एअरोस्पेस, ध्रुव स्पेस और दिगंतारा आदि हैं, जो छोटे उपग्रह बनाने या प्रक्षेपण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्काईरुट और अग्निकुल मांग के अनुरूप सिर्फ दो दिनों में छोटे उपग्रह प्रक्षेपित करने की सेवा दे सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आठ अरब डालर से बढ़ाकर 2033 तक 44 अरब डालर तक पहुंच जाए।



व्यक्तित्व

सविता : 19,400 फीट की ऊंचाई पर 265 किलोमीटर की दौड़

जनसत्ता संवाद

धातु विकास और पेशेवर पर्वतारोही सविता महतो ने 265 किलोमीटर लंबी 'लेह-मिंग ला अल्ट्रा रन' सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसके साथ ही वे इस बेहद कठिन उच्च हिमालयी 'अल्ट्रा एंडेवॉरर्स' दौड़ को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सविता ने 20 जुलाई को इस चुनौतीपूर्ण अभियान की शुरुआत की थी और छह दिनों की कठिन यात्रा के बाद 26 जुलाई को इसे पूरा किया। यह दौड़ करीब 19,400 फीट ऊंचे मिंग ला दर्रे से होकर गुजरती है, जहां धावकों को बेहद कम आक्सीजन, शून्य से नीचे तापमान, तेज हवाओं और कठिन पहाड़ी रास्तों जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सविता ने कहा 3,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर हर कदम चुनौतीपूर्ण होता है। जब शरीर जवाब देने लगता है, तब मन की ताकत ही आगे बढ़ने का हौसला देती है। यह उपलब्धि केवल एक खेल सफलता नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और अदम्य इच्छाशक्ति की अनुपम मिसाल है। इतनी ऊंचाई पर आक्सीजन की भारी कमी, बर्फीली हवाएं, शून्य के करीब तापमान, लगातार बदलता मौसम और दुर्गम रास्ते किसी भी एथलीट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में लगातार छह दिनों तक दौड़ते हुए लक्ष्य तक पहुंचना असाधारण माना जाता है।

बिहार के सागर जिले के पानापुर गांव में दियारा क्षेत्र की निवासी 30 वर्षीय सविता ने बताया कि इस सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, कड़ा प्रशिक्षण और मानसिक मजबूती है। उन्होंने इस दौड़ की तैयारी के लिए लगभग दो महीने तक ब्रास में अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने लंबी दूरी की दौड़, हाइकिंग और पर्वतारोहण के जरिए खुद को कठिन हिमालयी परिस्थितियों के लिए तैयार किया।

इस 'अल्ट्रा रन' के दौरान उन्होंने रोजाना करीब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उनका सफर लेह से शुरू होकर उपाशी, त्यो कार क्षेत्र, चुमाथांग, न्योमा और रोंग होते हुए मिंग ला तक पहुंचा। उन्होंने यह पूरी दौड़ अकेले पूरी की हालांकि अभियान के दौरान मेडिकल टीम, फिल्म निर्माताओं और लाजिस्टिक सहयोगियों की टीम उनके साथ रही।

सविता इससे पहले भी कई कठिन अभियानों में अपनी क्षमता साबित कर चुकी हैं। उन्होंने 570 किलोमीटर लंबी मनाली-उमलिंग ला अल्ट्रा रन 17 दिनों में पूरी की थी। इसके अलावा उन्होंने 1,200 किलोमीटर लंबी दिल्ली-उमलिंग ला साइकिल दौड़ अभियान को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। वर्ष 2014 से पेशेवर पर्वतारोहण से जुड़ी सविता ने 'हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट', दार्जिलिंग से प्रशिक्षण लिया है। वह लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश की सात हजार मीटर से अधिक ऊंची कई चोटियों पर चढ़ चुकी हैं।



(फाइल फोटो)

कमजोर कर दिया है। तटीय आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) और जंगलों का तेजी से विनाश उनके प्राकृतिक आवास छीन रहा है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बदलते स्वरूप और जंगली बिरलियों जैसी बाहरी हमलावर प्रजातियां भी इन प्रवासी पक्षियों के भविष्य को लगातार और अधिक असुरक्षित बना रही हैं।